



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 26-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2025 (MAGHA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 फरवरी, 2025

संख्या एम०आई०एस०सी०-57/2025/5115.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 को हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति अथवा उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से लिखित में नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा तृतीय संशोधन) नियम, 2024, कहे जा सकते हैं।
- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, अनुसूची IV के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(राज्य में नियन्त्रित क्षेत्रों में संपरिवर्तन प्रभार की दरें)

(प्रति वर्ग मीटर दरें रुपए में)

[illegible]

(क) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तक	1470	1260	1050	1260	1050	840	700	600	350	200	150	100
(ख) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से ऊपर	1715	1470	1225	1470	1225	980	816	700	408	235	175	116
औद्योगिक	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
एकीकृत अन्तर्देशीय आधान डिपो/कस्टम परिवर्द्ध क्षेत्र	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60
कृषि उत्पादों के लिए भाण्डागार	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
गैर कृषि उत्पादों के लिए भाण्डागार	150	150	150	120	120	120	75	75	75	45	45	45
संस्थागत	158	126	105	105	84	63	60	40	30	20	15	10
आमोद-प्रमोद	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60

टिप्पण :-

1. प्रयुक्त संकेताक्षर एन0एच0: नेशनल हाईवे, एस0आर0-शैड्यूलड रोड दर्शाते हैं।
2. सेक्टर सड़क विकास योजना पर दर्शाए अनुसार सेक्टर विभाजक सड़क है।
3. जहां भूमि का टुकड़ा एक प्रवर्ग से अधिक में पड़ता है, वहां पर उच्चतर/उच्चतम दर लागू होंगी।
4. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार प्रभारित किये जाएंगे।
5. हरियाणा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे कि सौर, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर, बायोमास कोजेनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-डीजल, पैलेटाइजेशन आदि के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार और संवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
6. आमोद-प्रमोद परियोजनाओं के भीतर वाणिज्यिक घटक जैसे होटल, प्रदर्शनी केन्द्रों, रेस्टोरेंट, सम्मेलन केन्द्र इत्यादि पर लागू वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जाएगी।
7. उद्यम प्रोन्नति नीति, 2015 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ख, ग और घ प्रवर्ग ब्लॉकस में पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे।
8. धार्मिक/आध्यात्मिक प्रवचन/नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थानों/संगठनों की दशा में, संपरिवर्तन प्रभार अनुमोदित आच्छादित क्षेत्र/ फर्श क्षेत्र अनुपात के अनुसार ऊर्जा उद्गृहीत होंगे।
9. ट्रांजिट ओरियंटड विकास की दशा में, संपरिवर्तन प्रभार यथानुपात आधार पर उद्गृहीत किए जाएंगे अर्थात् 0.25 फर्श क्षेत्र अनुपात के प्रत्येक बड़े हुए स्लैब के लिए अनुसूची-IV संबंधित उपयोग के लिए प्रभार विहित दरों के अनुसार 25 प्रतिशत के लिए लागू प्रभारों के बराबर अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे। तथापि संपरिवर्तन प्रभार का पूरा भुगतान ट्रांजिट ओरियंटड विकास पालिसी के अधीन नई अनुज्ञप्तियों हेतु भुगतान योग्य होगा।
10. मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना के मामले में, संपरिवर्तन प्रभार उपयोगों के अनुपात में उद्गृहीत किए जाएंगे।
11. नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के लिए संपरिवर्तन प्रभार, 1.0 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में आवासीय प्लॉटिड कालोनी के लिए विहित दर के 1.5 गुणा और 1.25 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में 2.0 गुणा की दर से उद्गृहीत किए जाएंगे।
12. दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन स्वीकृत प्लॉटिड आवासीय उपनिवेशों के लिए, संपरिवर्तन प्रभारों की छूट दी गई है।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची IV—ख के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची IV—ख

[देखिए नियम 26—घ (छ)]

पंचकूला जिले में नियन्त्रित क्षेत्रों में संपरिवर्तन प्रभारों की दरें

(प्रति वर्गमीटर दरें रुपये में)

क्षमता जोन	उच्च क्षमता			निम्न क्षमता		
1	2			3		
नियन्त्रित क्षेत्र का नाम	पंचकूला के परिधि नियन्त्रित क्षेत्र			पंचकूला जिले में घोषित अन्य सभी नियन्त्रित क्षेत्र		
	साथ लगते हुए			साथ लगते हुए		
उपयोग	राष्ट्रीय राजमार्ग	अनुसूचित सड़क/सैक्टर सड़क	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	अनुसूचित सड़क/सैक्टर सड़क	अन्य सड़क
आवासीय	204	163	122	30	20	15
आवासीय प्लॉटिड उपनिवेश	204	163	122			
आवासीय ग्रुप आवास उपनिवेश	285	245	204			
निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश	204	163	122	30	20	15
वाणिज्यिक उपनिवेश	815	713	612	.	.	.
वाणिज्यिक उपनिवेश 150% फर्श क्षेत्र अनुपात से अधिक	.	.	.	235	175	116
वाणिज्यिक उपनिवेश 150% फर्श क्षेत्र अनुपात तक	.	.	.	200	150	100
औद्योगिक उपनिवेश/ औद्योगिक/ कृषि उत्पादों के लिए भण्डागार/ गैर-कृषि उत्पादों के लिए भण्डागार/ गोदाम/ शीतगृह	17	17	17	17	17	17
एकीकृत अन्तर्देशीय आधान डिपो/कस्टम परिवर्द्ध क्षेत्र	160	160	160	60	60	60
बैंकट हाल	790	790	564	175	150	125
पेट्रोल पंप/संपीडित प्राकृतिक गैस/पाइप प्राकृतिक गैस	336	269	202	200	150	100
अस्पताल	61	61	61	20	15	10
होटल	61	61	61	61	61	61
संस्थागत	31	31	31	20	15	10
आमोद—प्रमोद	92	61	31	60	60	31
150% फर्श क्षेत्र अनुपात हेतु शहरीकरण योग्य क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाएं तथा कृषि अंचल में बैंकट हाल की सुविधा सहित मोटल, रिजार्ट	2115	1851	1586	.	.	.
कृषि अंचल में अन्य वाणिज्यिक परियोजनाएं जो ऊपर वर्णित नहीं की गई हैं,						
(क) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात तक	1260	1050	840	.	.	.
(ख) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात से अधिक	1470	1225	980	.	.	.

कृषि अंचल में 150% फर्श क्षेत्र अनुपात हेतु वाणिज्यिक परियोजनाएँ तथा बैंकट हाल की सुविधा सहित मोटल, रिजर्ट	.	.	.	350	300	250
अन्य वाणिज्यिक परियोजनाएँ जो ऊपर वर्णित नहीं की गई हैं,						
(क) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात तक	.	.	.	200	150	100
(ख) 150% फर्श क्षेत्र अनुपात से अधिक	.	.	.	235	175	116

टिप्पण :—

1. प्रयुक्त संकेताक्षर एन0एच0: नेशनल हाईवे, एस0आर0— शैड्यूल रोड दर्शाते हैं।
2. सेक्टर सड़क विकास योजना पर दर्शाये अनुसार सेक्टर विभाजक सड़क है।
3. जहां भूमि का टुकड़ा एक प्रवर्ग से अधिक में पड़ता है, वहां पर उच्चतर/उच्चतम दर लागू होगी।
4. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार प्रभारित किए जाएंगे।
5. हरियाणा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे कि सौर, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर, बायोमास कोजेनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो—डीजल, पैलेटाइजेशन आदि के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार और संवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
6. आमोद—प्रमोद परियोजनाओं के भीतर वाणिज्यिक घटक जैसे होटल, प्रदर्शनी केन्द्रों, रेस्टोरेंट, सम्मेलन केन्द्र इत्यादि पर लागू वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जाएगी।
7. उद्यम प्रोन्नति नीति, 2015 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ख, ग और घ प्रवर्ग ब्लॉकस में पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे।
8. धार्मिक/आध्यात्मिक प्रवचन/नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं/संगठनों की दशा में, संपरिवर्तन प्रभार अनुमोदित आच्छादित क्षेत्र/फर्श क्षेत्र अनुपात के अनुसार उद्गृहीत होंगे।
9. ट्रांजिट ओरियंटिड विकास की दशा में, संपरिवर्तन प्रभार यथानुपात आधार पर उद्गृहीत किए जाएंगे अर्थात् 0.25 फर्श क्षेत्र अनुपात के प्रत्येक बढ़े हुए स्लैब के लिए संबंधित उपयोग के लिए प्रभार विहित दरों के अनुसार 25 प्रतिशत के लिए लागू प्रभारों के अनुसूची—IV बराबर अतिरिक्त शुल्क के लागू होंगे। तथापि, संपरिवर्तन प्रभार का पूरा भुगतान ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पालिसी के अधीन नई अनुज्ञप्तियों हेतु भुगतान योग्य होगा।
10. मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना के मामले में परिवर्तन प्रभार उपयोगों के अनुपात में ऊर्जा उद्गृहीत किए जाएंगे।
11. नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के लिए आवासीय घटकों पर संपरिवर्तन प्रभार, प्रस्तावित फर्श क्षेत्र अनुपात अर्थात् वर्ग आवासीय कालोनी के लिए अधिसूचित तत्स्थानी दरों के 5/7 की दर के अनुपात में वसूल किए जाएंगे।
12. दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन स्वीकृत प्लॉटिड आवासीय उपनिवेश के लिए संपरिवर्तन प्रभारों की छूट दी गई है।

अपूर्व कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 6th February, 2025

No. Misc-57/2025/5115.— The following draft rules further amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of rules, before the expiry of the period so specified:-

Draft Rules

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Third Amendment) Rules, 2024.
2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, (hereinafter called the said rules), for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely: —

Schedule IV

[See rule 26-D (g)]

RATES OF CONVERSION CHARGES IN THE CONTROLLED AREAS IN THE STATE

(Rates in Rupees per square meter)

Potential Zone	Hyper Potential			High Potential			Medium Potential			Low Potential		
1	2			3			4			5		
Name of Controlled Area	Controlled areas forming part of the Development Plan Gurgaon-Manesar Urban Complex.			Controlled areas declared in Gurgaon District excluding the controlled areas forming part of the Development Plan Gurgaon-Manesar Urban Complex and controlled area forming part of Development Plan of Pataudi and Farukhnagar but including part of Sohna Development Plan, controlled areas of Faridabad-Ballabgarh Complex, controlled areas of Sonipat-Kundli Multifunctional Urban Complex, Panipat.			Controlled areas around towns i.e. Karnal, Kurukshetra, Ambala City, Ambala Cantt., Yamuna Nagar, Jagadhri, Bahadurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Bawal-Dharuhera Complex, Gannaur, Palwal, Hodel, Controlled areas declared in Faridabad District (excluding the controlled areas of Faridabad-Ballabgarh Complex), Oil refinery Panipat (Beholi) and Controlled Areas forming part of the Development Plan, Prithla.			All other controlled areas declared in the State.		
	Abutting on			Abutting on			Abutting on			Abutting on		
Use	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road
Residential	210	158	105	158	125	105	100	80	60	30	20	15
Low Density Eco Friendly Colonies	210	158	105	158	125	105	100	80	60	30	20	15
Commercial												
i. Commercial Projects like Motel with Banquet facility, 5-Star Hotel,	4700	4500	4300	2600	2400	2200	1200	1100	800	350	300	250

Resort for 150% Floor Area Ratio (FAR) Permission granted under provisions of Punjab Act No. 41 of 1963												
ii. Other Commercial Projects, which are not mentioned above.												
(a) upto 150% FAR	1470	1260	1050	1260	1050	840	700	600	350	200	150	100
(b) above 150% FAR	1715	1470	1225	1470	1225	980	816	700	408	235	175	116
Industrial	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
Integrated Inland Container Depots/Custom Bounded Areas	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60
Warehouses for agro-produces	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
Warehouses other than agricultural	150	150	150	120	120	120	75	75	75	45	45	45
Institutional	158	126	105	105	84	63	60	40	30	20	15	10
Recreational	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60

Notes:

1. Abbreviations used indicate NH: National Highway; SR: Scheduled Road.
2. Sector Road is the Sector dividing road as indicated on the Development Plan.
3. Where a piece of land falls in more than one category, the Higher/Highest rate shall apply.
4. 50 percent conversion charges shall be charged for food processing unit located in industrially backward area declared by the Industries Department, Haryana.
5. No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy projects in the State of Haryana registered with the New and Renewable Energy Department of the State of Haryana viz. Solar, Hydro, Biogas, Biomass Power, Biomass Cogeneration, Green Hydrogen, Bio-Diesel, Palletisation etc.
6. The commercial components like hotels, exhibition centers, restaurants, convention centers etc. shall be charged at applicable commercial rates within the recreational projects.
7. 50% conversion charges shall be levied in B, C&D category blocks as notified by the Government, for Micro, Small and Medium Enterprise as defined in the Enterprises Promotion Policy-2015.
8. In case of Institutions/Organizations imparting religious/spiritual preaching/moral education, the conversion charges be levied as per covered area/FAR approved.
9. In case of Transit Oriented Development, the conversion charges shall be levied on pro-rata basis i.e. for every increased slab of 0.25 FAR, the additional charges equivalent to the charges applicable for

FAR of 25% as per the rates prescribed for respective use in Schedule-IV shall be applicable. However, full payment of conversion charges shall be payable for fresh licences under Transit Oriented Development Policy.

10. The conversion charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use projects.
 11. For New integrated Licencing Policy, the conversion charges shall be levied 1.5 times the rate prescribed for residential plotted colony in case of 1.0 FAR and 2.0 times in case of 1.25 FAR.
 12. For Affordable Plotted Residential Colonies permitted under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the conversion charges are exempted.”;
3. In the said rules, for Schedule IV-B, the following Schedule shall be substituted, namely: -

“Schedule IV-B

[see rule 26-D (g)]

RATES OF CONVERSION CHARGES IN THE CONTROLLED AREAS IN PANCHKULA DISTRICT

(Rates in Rupees per square metre)

Potential Zone	High Potential			Low Potential		
1	2			3		
Name of the Controlled Area	Periphery Controlled Area of Panchkula			All other controlled Area declared in Panchkula district		
	Abutting on			Abutting on		
Use	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road
Residential	204	163	122	30	20	15
Residential Plotted Colony	204	163	122			
Residential Group Housing colony	285	245	204			
Low density Eco Friendly Colony	204	163	122	30	20	15
Commercial Colony	815	713	612	-	-	-
Commercial Colony above 150 Floor Area Ratio (FAR)	-	-	-	235	175	116
Commercial Colony upto 150 Floor Area Ratio (FAR)	-	-	-	200	150	100
Industrial Colony/industrial/ Warehouses for Agro Produces / Warehouses other than agriculture produces / Godown /Cold store	17	17	17	17	17	17
Integrated in land container depots/Custom bounded areas	160	160	160	60	60	60
Banquet Hall	790	790	564	175	150	125
Petrol Pump / CNG / PNG	336	269	202	200	150	100
Hospital	61	61	61	20	15	10
Hotels	61	61	61	61	61	61
Institutional	31	31	31	20	15	10
Recreational	92	61	31	60	60	31
Commercial projects in urbanisable zone and Motel with banquet facility, resort for 150% FAR in agriculture zone	2115	1851	1586	-	-	-
Other commercial projects in agriculture zone which are not mentioned above						

(a) Upto 150% FAR	1260	1050	840	-	-	-
(b) Above 150 FAR	1470	1225	980	-	-	-
Commercial projects like Motel with banquet facility, resort for 150% FAR in agriculture zone	-	-	-	350	300	250
Other commercial projects which are not mentioned above						
(a) Upto 150% FAR	-	-	-	200	150	100
(b) Above 150 FAR	-	-	-	235	175	116

Notes:

1. Abbreviations used indicate NH: National Highway; SR: Scheduled Road.
2. Sector Road is the Sector dividing road as indicated on the Development Plan.
3. Where a piece of land falls in more than one category, the Higher/Highest rate shall apply.
4. 50 percent conversion charges shall be charged for food processing unit located in industrially backward area declared by the Industries Department, Haryana.
5. No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy projects in the State of Haryana registered with the New and Renewable Energy Department of the State of Haryana viz. Solar, Hydro, Biogas, Biomass Power, Biomass Cogeneration, Green Hydrogen, Bio-Diesel, Palletisation etc.
6. 50% conversion charges shall be levied in B, C&D category blocks as notified by the Government, for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Enterprises Promotion Policy-2015.
7. In case of Institutions/Organizations imparting religious/spiritual preaching/moral education, the conversion charges be levied as per covered area/FAR approved.
8. In case of Transit Oriented Development, the conversion charges shall be levied on pro-rata basis i.e. for every increased slab of 0.25 FAR, the additional charges equivalent to the charges applicable for FAR of 25% as per the rates prescribed for respective use in Schedule-IV shall be applicable. However, full payment of conversion charges shall be payable for fresh licences under Transit Oriented Development Policy.
9. The conversion charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use project.
10. For New Integrated Licencing Policy, the conversion charges on the residential component shall be recovered in proportion to the proposed FAR i.e. at 5/7th of the corresponding rates notified for group housing colonies.
11. For Affordable Plotted Residential Colonies permitted under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the conversion charges are exempted.”

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.